एयर इंडिया भारी संकट में, सात फ्लाइट्स एक साथ रद्द की गई

शिलांग, 17 जून। एअर इंडिया की परेशानियां मंगलवार को तब और बढ़ गईं, जब तकनीकी और परिचालन कारणों से सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। यह टाटा समूह के एयरलाइन खरीदने के बाद सबसे गंभीर संकट माना जा रहा है। छह उड़ानें इसलिए रद्द की गईं, क्योंकि डीजीसीए ने ड्रीमलाइनर बेड़े की अतिरिक्त जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली उड़ान विमान उपलब्ध न होने के कारण रद्द की गई।

- **एयर इंडिया, जिसका संचालन टाटा ग्रुप के पास है, ने यात्रियों से खेद जताया और वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया।**

एअर इंडिया ने कहा कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उसकी उड़ान रद्द कर दी गई है। एयरलाइन की ओर से इसके पीछे के कारण विमान की अनुपलब्धता, हवाई क्षेत्र में पाबंदियां और अतिरिक्त सावधानी से की जा रही जांच बताई गई। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं लिया गया। एअर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया और कहा कि उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।

इस वर्ष "राइज़िंग राजस्थान कॉन्क्लेव" 11 व 12 दिसम्बर को होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कॉन्क्लेव में प्रदेश में आये औद्योगिक/आर्थिक बदलावों की विस्तृत जानकारी दी जायेगी

जयपुर, 17 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की अहम भूमिका है। पिछले वर्ष हुए इस आयोजन ने निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ और राजस्थान प्रमुख निवेश केन्द्र के रूप में उभरा है। इसी कड़ी में जयपुर में 11 व 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली "राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025" प्रदेश की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश साझेदारी को और मजबूत करेगी।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हुए एमओयू की क्रियान्विति से प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य में आए बदलावों के बारे में निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कॉन्क्लेव में सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट और इन्डस्ट्री टू इन्डस्ट्री के आधार पर राजस्थान एवं अन्य राज्यों तथा देशों के मध्य निवेश साझेदारी विकसित की जाए, जिससे प्रदेश के विकास को नए आयाम मिलें।

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव का मुख्य लक्ष्य 2024 में हुए समिट में हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति का विवरण पेश करना व 2026 में होने वाले समिट के लिए हमारा विज़न पेश करना है।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव का प्रमुख लक्ष्य राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हस्ताक्षिरत हुए एमओयू की प्रगति का विवरण पेश करने के साथ ही, वर्ष 2026 के प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर हमारे विजन को प्रस्तुत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव से पूर्व राज्य सरकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रनअप कार्यक्रमों के साथ ही, थीमेटिक विभागीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राइज़िंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कॉन्क्लेव में सिटी टु सिटी, स्टेट टु स्टेट और इन्डस्ट्री टु इन्डस्ट्री के आधार पर राजस्थान एवं अन्य राज्यों तथा देशों के मध्य निवेश साझेदारी विकसित की जाए।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दो दिवसीय पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, राउण्ड टेबल और फायरसाइट चैट के साथ ही, एंकर इन्वेस्टर्स सम्मेलनों का आयोजन प्रस्तावित है।

लगातार दूसरे दिन करोना के एक्टिव केस घटे

नयी दिल्ली, 17 जून। देश में पिछले तीन दिनों के दौरान करोना के सक्रिय मामलों में कमी देखी गयी है और मंगलवार सुबह तक सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6836 रह गयी है। इससे पहले रविवार और सोमवार को कुल सक्रिय मामलों की संख्या क्रमशः 7383 और 7264 थी।

पिछले 24 घंटों के दौरान, करोना संक्रमण से एक और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 109 पहुंच गया और 428 मामले घटने के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6836 रह गयी। वहीं, 1168 मरीजों के स्वस्थ होने से अभी तक इस वायरस से निजात पाने वालों की कुल संख्या 14772 पहुंच गयी है। गत 22 मई को देश में कोराना के मामले सिर्फ़ 257 सक्रिय थे।

- **रविवार व सोमवार को करोना के एक्टिव केस क्रमशः 7383 और 7264 थे जो मंगलवार को घटकर 6836 रह गए।**

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरान संक्रमण से एक मरीज की मौत हुयी है।

इस अवधि में जहां 14 राज्यों और केन्दशासित प्रदेशों में करोना के मामलों में वृद्धि देखी गई, वहीं 11 राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी आयी है।

ट्रंप जी 7 शिखर वार्ता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पास ऐसा शक्तिशाली बम है, जिसे - 52 विमान द्वारा छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब तक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इसका प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थीं।

ट्रंप ने जी7 शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों से कहा कि ईरान के पास अब भी बातचीत की मेज पर लौटने का विकल्प मौजूद है, ताकि एक नया परमाणु समझौता हो सके। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सीमित संघर्ष विराम की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो ईरान परमाणु समझौते पर इतने व्यापक हमले नहीं कर सकता था। इन हमलों में ईरान की सुरक्षा और सैन्य कमान के सभी शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं, जिससे ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनी की दशकों पुरानी सत्ता को गंभीर झटका लगा है।

डॉनल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाज़ी कर रहे थे और उन्होंने "अभूतपूर्व परिणामों" की चेतावनी दी थी यदि ईरान ने परमाणु हथियारों की दिशा में अपने प्रयास नहीं रोके। उन्होंने ईरानी शासन से कहा था कि यदि वह विनाशकारी अमेरिकी हमलों से बचना चाहता है, तो

- **ट्रंप अब ईरान से "डील" करना चाहते हैं कि अगर ईरान "नेगोशिएटिंग टेबल" पर "डील" करने नहीं आता है तो अमेरिका इज़रायल को बी-52 विमान ईरान के खिलाफ काम में लेने की अनुमति दे देगा।**
- **अमेरिका का ईरान पर यह दबाव शायद चल जाएगा, ट्रंप को यह विश्वास है। इसीलिए ट्रंप गत कुछ दिनों से लगातार ईरान को बार-बार धमका रहे हैं।**
- **जी 7 शिखर सम्मेलन से ट्रंप की अचानक विदाई को चुपचाप स्वीकार करने के अलावा जी7 ग्रुप के अन्य सदस्यों के पास कोई चारा नहीं था।**

बातचीत के लिए तैयार हो, या फिर उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इज़राइल का मानना है कि ईरान उसके खिलाफ परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, और इस आधार पर उसने आत्मरक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए हमलों को उचित ठहराया है।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी स्वीकृति के बिना इज़राइल उसे तुरंत बातचीत की प्रक्रिया में लौटना होगा।

जी7 के अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के अचानक रवाना होने को स्वीकार किया। शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरे जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तावित थी।

शुरु से लग रहा था, पता नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

अगर ईरान ने इज़रायल को ही नहीं, पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को सजा देने का सोचा तो इसके गंभीर नतीज़े हो सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ईरान ने पर्शियन खाड़ी को बंद करने की कोशिश की, जिससे तेल से लदे जहाजों का मार्ग अवरुद्ध हो, तो इससे वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसा कदम मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उनके पास तेल निर्यात का कोई अन्य आसान रास्ता नहीं होगा।

जी7 की तत्काल चिंता का विषय यह भी है कि इस संघर्ष का असर रूस-यूक्रेन युद्ध पर कैसे पड़ेगा। जी7 देश रूसी तेल कीमतों पर सीमा निर्धारित कर रूस की आमदनी कम करना चाहते हैं, ताकि उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सके, क्योंकि तेल बेचकर रूस जो पैसा कमा रहा है, उससे ही युद्ध को फायनैंस कर रहा है।

लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो रूस पर और प्रतिबंध लगाने के इच्छुक नहीं दिखते। जी-7 देश भी ट्रंप के इस रूख को अच्छी तरह से समझते हैं।

ट्रंप की इकतरफा नीतियों और सहयोगियों की अनदेखी के चलते, पहले भी जी7 बैठकों में गतिरोध पैदा हुआ है। पिछली बार जब जी7 सम्मेलन कैनडा में हुआ था, ट्रंप ने संयुक्त घोषणा पत्र को समर्थन देने से इनकार कर दिया था और बाद में कथित तौर पर उस दस्तावेज को फाड़ भी दिया था। उस समय कैनडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को उन्होंने "कायर" तक कह दिया था।

हालांकि इस बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जैसे नेता मौजूद हैं, जो पहले ऑवल ऑफिस में ट्रंप के सामने सीधे खड़े हो चुके हैं।

इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस बार बैठक पर कितना प्रभाव डालते हैं, और क्या कोई प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे।

नाबालिग का अपहरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के चाचा ने 7 जुलाई, 2020 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी भतीजी 4 जुलाई को अपने घर के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में उसे गांव के दो युवक मिले और पीड़िता को घर छोडने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए। इस दौरान अभियुक्त नितिन भी रास्ते में मिला और वह भी उसने साथ-साथ गांव गया। भतीजी को घर छोड़ने के बजाए उसे धर्मशाला ले गए और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, उसे एक धार्मिक स्थल के तिबारे में रात भर रखा और दुष्कर्म किया। वहीं, सुबह उसे नशीला पेय पिलाकर वहां छोड़कर चले गए। रास्ते में बदहवास भतीजी को देखकर लोगों ने उसे फोन पर सूचना दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ अभियुक्त नितिन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

कच्चे तेल के परिवहन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के माध्यम से, टैंकरों द्वारा उतारे गए कच्चे तेल की लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह संचालन से लाभ होगा।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर शैडो फ्लीट्स और विशेष रूप से रूसी कच्चे तेल के परिवहन पर निगरानी और कड़ी हो रही है। भारत द्वारा अपने स्वदेशी टैंकरों का निर्माण और संचालन इस दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है-जो विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहता है।

हालांकि आलोचकों का कहना है कि भले ही यह टैंकर सरकारी नियंत्रण में बनेंगे, लेकिन इसका वास्तविक नियंत्रण धीरे-धीरे निजी हाथों में जा सकता है। इसके कारण सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से निजी एकाधिकार के बढ़ते खतरे और क्रोनी कैपिटलिज़्म (मित्र पूंजीवाद) की आशंका जताई जा रही है।

जहां एक ओर यह परियोजना स्वदेशी निर्माण, रोजगार और समुद्री क्षमता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय और परिचालन नियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस और अडानी जैसे औद्योगिक दिग्गजों को जाता दिख रहा है।

भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकारी पहलों और निजी एकीकरण के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है-यह ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी तारीफ तो बनती है पर इसकी जांच भी की जानी चाहिए। जो प्रशंसा और जांच, दोनों की हकदार है।

'कुछ देर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाक के सशस्त्र तनाव के दौरान, बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित रही। वहीं, लाइब्रेरी आदि को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए। वहीं, एक्स सर्विसमैन कोटे में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों को पुनः ड्यूटी पर बुला लिया गया था। इसके चलते उन्हें भी अध्ययन का मौका नहीं मिला। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी पूर्व में भी कई बार मुख्य परीक्षा को स्थगित कर चुका है। एक भर्ती में तो मुख्य परीक्षा की तिथि से दो दिन पूर्व ही भर्ती स्थगित की गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए मंगलवार से होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600